

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,  
उपसचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां,  
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 07 दिसम्बर, 2010  
विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 के सहकारिता विभाग के आयोजनेतर पक्ष की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5219/लेखा-बजट/2010-11/दिनांक 22 नवम्बर, 2010, वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या:-187/XXVII (1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 एवं शासनादेश संख्या-1168/XIV-1/2010-5(30)/2010 दिनांक 07 सितम्बर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में सहकारिता विभाग के आयोजनेतर पक्ष में कुल धनराशि ₹ 16,00,000/- (रु० सोलह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय। छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2010-11 में देय वेतन/पेंशन एरियर की अन्तिम किश्त की धनराशि का भुगतान शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह में 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।



6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2- उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता आयोजनेत्तर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की निम्नलिखित सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा:-

(धनराशि हजार रू0 में)

01- वेतन	1500
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	100
योग-	1600

(रूपये सोलह लाख मात्र)

3:- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-217(NP)/XXVII (4)/2010 दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
उपसचिव।

संख्या:- १९१९ (1)/XIV-1/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रभारी मिडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फ़ावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
उपसचिव।